फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 292 प्रभात जयपुर, मंगलवार 26 मई, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Rashtradoot Metro

epaper.rashtradoot.com

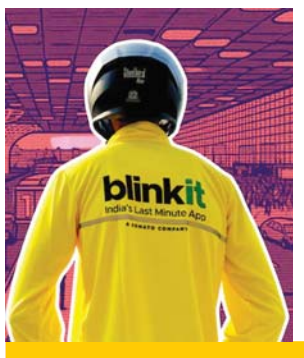

Will Blinkit entry bring down...

The likely outcome is coexistence, not disruption. Blinkit will emerge as an additional layer of convenience, particularly for price-sensitive travellers

Do Gaz Zameen

Christ and Caiaphas | A source of light in a very dark place. A way forward in hard times. And maybe, even the light of god, when you would need it the most

ताश के पत्तों के महल की तरह बिखर गई, अजेय रही टीएमसी

फाल्टा उपचुनाव के नतीजे ने अभिषेक और ममता बनर्जी के अभिमान को चूर-चूर कर दिया

- अंजन रॉय -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली 25 मई। रविवार को तृणमूल के चर्चित फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव नतीजों ने अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक गर्व को बड़ा झटका दिया। इस सीट पर भाजपा ने भारी और चौंकाने वाली जीत दर्ज की। अभिषेक बनर्जी ने खुद अपने संसदीय चुनाव में इसी तरह की बड़ी जीत हासिल की थी।

फाल्टा के नतीजों ने चुनाव लड़ने के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को ध्वस्त कर दिया है। आरोप है कि इस मॉडल में लोगों को स्वतंत्र रूप से वोट नहीं डालने दिया जाता था। कहा जाता है कि अभिषेक बनर्जी की टीम ने हिंसा की, लोगों पर हमले किए और सत्तारूढ़ दल के पक्ष में फर्जी मतदान कराया।

भाजपा को 1,39,000 वोट मिले, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंद्वी आईएसएफ-सीपीआई (एम) उम्मीदवार को लगभग 37,000 वोट मिले। तीसरे स्थान पर रही कांग्रेस को 6,700 वोट मिले और तृणमूल उम्मीदवार, जिसे अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता था, को केवल लगभग 4,000 वोट मिले।

फाल्टा और अन्य जगहों के मतदान रुझानों ने दिखाया कि पूरे चुनाव में हिंदू वोटों का पूरी तरह ध्रुवीकरण हुआ। बड़ी संख्या में हिंदू मतदाता भाजपा के साथ गए, जबकि मुस्लिम वोट आईएसएफ-सीपीआई(एम) उम्मीदवार के पक्ष में चले गए। इससे साफ संकेत मिला कि अल्पसंख्यक वोटर बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस से दूर हो गए हैं।

इसके बाद फाल्टा नगरपालिका के सभी तृणमूल पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। पूरे राज्य में सात नगरपालिकाओं के 115 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे ये नगरपालिकाएं नेतृत्वविहीन हो गईं। नई भाजपा सरकार के पास अब प्रशासक नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- फाल्टा के वोटिंग पैटर्न से एक बात तो साफ है कि मुसलमानों ने भी तृणमूल कांग्रेस से दूरी बना ली है और इन नतीजों के बाद फाल्टा नगरपालिका के सभी पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया।
- तृणमूल के जिन कार्यकर्ताओं से पहले लोग थर-थर कांपते थे, उन्हें घेर कर पीटा जा रहा है, चोर-चोर के नारे लगाए जा रहे हैं।
- ममता बनर्जी और तृणमूल के विशाल प्रतीक चिन्हों को या तो हटा दिया गया या तोड़ दिया गया।
- ममता बनर्जी की पुरानी विश्वस्त सहयोगी संसद में सर्वाधिक मुखर सांसद रहीं काकोली दास गुप्ता ने ममता बनर्जी से संबंध तोड़ने की घोषणा की।

जिमखाना क्लब के मसले पर आज होगी सुनवाई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 मई। दिल्ली जिमखाना क्लब ने सोमवार को केन्द्र सरकार द्वारा जारी उस नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें उसे अपने परिसर को खाली करने का निर्देश दिया गया है। क्लब की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन की अदालत में मामले का उल्लेख करते हुए त्वरित सुनवाई की मांग की। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 26 मई, मंगलवार को तय की।

- क्लब की तरफ से विजय खुराना ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जिमखाना की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी करेंगे।

याचिका में कहा गया है कि केन्द्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली के केन्द्र में स्थित 2, सफदरजंग रोड पर बने दिल्ली जिमखाना क्लब को सार्वजनिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए 5 जून तक 27.3 एकड़ में फैले अपने परिसर को खाली करने का नोटिस जारी किया है। यह याचिका विजय खुराना ने दिल्ली जिमखाना क्लब की ओर से दायर की है। याचिका

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूपी भाजपा में भारी संगठनात्मक फेरबदल की तैयारी

यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह चौधरी, महासचिव विनोद तावड़े से चर्चा के लिए नई दिल्ली पहुँचे

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 मई। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लड़ाई के पाले खींचे जा रहे हैं। भाजपा ने बड़े संगठनात्मक बदलावों की प्रक्रिया शुरू कर दी है, वहीं विपक्षी दल (कांग्रेस और समाजवादी पार्टी) भी जल्द समझौता करने को लेकर बेचैन दिखाई दे रहे हैं।

खुद को आगे बनाए रखने की कोशिश में, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी सोमवार को उत्तर प्रदेश भाजपा इकाई के पुनर्गठन पर भाजपा महासचिव विनोद तावड़े से चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचे। बड़े स्तर पर फेरबदल की तैयारी दिखाई दे रही है। सूत्रों के अनुसार, बड़ी संख्या में वर्तमान पदाधिकारियों के बड़े हिस्से को हटाया जा सकता है। ऐसी संभावना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे पंकज सिंह को हटाकर उनकी जगह बड़े बेटे नीरज सिंह को जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव को भी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, पंकज चौधरी पहले ही भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित, वरिष्ठ नेताओं से विस्तृत चर्चा कर चुके हैं।

इसी बीच, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अनौपचारिक बातचीत भी शुरू हो गई है। दोनों दल जल्दी ही गठबंधन बनाने के इच्छुक दिखाई दे रहे हैं, खासकर बिहार के अनुभव को देखते हुए। बिहार में राजद के साथ सीट बंटवारे में देरी से राजनीतिक नुकसान हुआ था, जिससे दोनों दलों की संभावनाएँ प्रभावित हुई थीं।

2024 के लोकसभा चुनावों में सपा-कांग्रेस गठबंधन के उत्साहजनक प्रदर्शन, जिसमें गठबंधन ने राज्य की 80 में से 43 सीटें जीती थीं, के बाद यह व्यापक समझ बनी है कि दोनों दलों को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- चर्चा है कि बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों को पद से हटाया जाएगा, यह भी चर्चा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे पंकज सिंह को हटाकर उनके बड़े बेटे नीरज सिंह को बड़ा पद दिया जा सकता है।
- कांग्रेस और सपा ने भी सीटों के बंटवारे पर अनौपचारिक वार्ता शुरु कर दी है। दोनों पार्टियाँ सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला जल्द से जल्द तय कर लेना चाहती हैं, खासकर बिहार के अनुभव को देखते हुए, जहाँ सीटों के बंटवारे में देरी होने से आरजेडी और कांग्रेस दोनों को ही भारी नुकसान हुआ था।

कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्धारमैया को दिल्ली तलब किया

डीके शिवकुमार को नहीं बुलाया, इससे कर्नाटक में अटकलों का बाज़ार गर्म है

- जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली 25 मई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने कैबिनेट सहयोगियों और करीबी सहायकों के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं, जिससे राज्य नेतृत्व में बदलाव की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली बैठक में चर्चा का विषय उन्हें ज्ञात नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "मुझे दिल्ली बुलाया गया है। चर्चा का विषय क्या है, मुझे नहीं पता। मेरी बैठक सुबह 11 बजे (मंगलवार) निर्धारित है। अटकलें तो लगती ही रहेंगी"। उनके इस बयान को उनके और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच नेतृत्व संघर्ष के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को दिल्ली बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। राजनीतिक हलचल पर प्रतिक्रिया देते हुए डीके शिवकुमार ने कहा, "अगर हाईकमान बुलाएगा तो दिल्ली जाऊंगा। मुख्यमंत्री बदलने पर टिप्पणी करना मेरा काम नहीं है"।

इस वर्ष जनवरी में सिद्धारमैया ने इतिहास रचते हुए कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया था, तथा कांग्रेस के दिग्गज नेता डी देवराज अर्स का रिकॉर्ड तोड़ा था।

कर्नाटक में लंबे समय से चल रहा सिद्धारमैया बनाम डीके शिवकुमार सत्ता संघर्ष अब नए मोड़ पर पहुंच सकता है। इससे पहले सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया था कि मई के अंत में होने वाली बैठक में "सभी मुद्दों" का समाधान कर दिया जाएगा।

गुरुवार को संभावित नेतृत्व परिवर्तन के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने रहस्यमय अंदाज में कहा था, "अच्छा समय आएगा"।

यह संकट पहली बार पिछले साल नवंबर में कांग्रेस सरकार के ढाई वर्ष पूरे होने पर सामने आया था।

शिवकुमार खेमे ने हाईकमान को उस कथित सत्ता-साझेदारी फार्मूले की याद दिलाई थी, जिस पर 2023 में राज्य में कांग्रेस की जीत के बाद सहमति बनी थी। इसके बाद कांग्रेस ने दोनों गुटों के साथ कई बैठकों करके, और डीके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- गत दिनों नेतृत्व परिवर्तन के बारे में पूछे जाने पर डीके शिवकुमार ने पहेलीनुमा जवाब दिया था, अच्छा समय आएगा, तब उनके समर्थकों ने कांग्रेस मुख्यालय पर शिवकुमार को "नैक्स्ट सीएम" करार देते हुए पोस्टर भी लगाए थे।

बी-2 बाईपास पर तोड़फोड़ की कार्यवाही पर पुनः रोक

जयपुर, 25 मई। सुप्रीम कोर्ट ने टोंक रोड बी 2 बाईपास स्थित 42 बीघा भूमि से जुड़े मामले में हाउसिंग बोर्ड की आगामी कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

- सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश देते हुए कहा कि तोड़फोड़ की कार्यवाही से पूर्व सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अदालत के समक्ष रोक हटाने का प्रार्थना पत्र आता है तो अदालत सभी पक्षकारों को सुनने के बाद ही निर्णय लेगी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जयपुर में पेट्रोल 112 रूपए और डीज़ल 95 रूपए प्रति लीटर पहुँचा

दो सप्ताह में लगातार चौथी बार पेट्रोल-डीज़ल के दामों में भारी वृद्धि हुई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 मई। भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है।

पिछले दो सप्ताह में ईंधन कीमतों में यह चौथी बढ़ोतरी है, जिससे कुल वृद्धि लगभग 7.5 रुपये तक पहुंच गई है। सरकारी तेल कंपनियां वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद लंबे समय तक दरें स्थिर रखने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए लगातार संशोधन कर रही हैं।

इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण अमेरिका और ईरान के बीच जारी पश्चिम एशियाई संघर्ष को माना जा रहा है, जिसके चलते होर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो गया है।

ताजा वृद्धि के बाद, नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रभाव पर बोलते हुए ओएनजीसी की निदेशक (अन्वेषण) सुषमा रावत ने कहा कि स्थिति को लेकर अनिश्चितता के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

रावत ने कहा, "जब भी शांति समझौते की घोषणा होती है, कच्चे तेल की कीमतें गिरने लगती हैं। लेकिन जब यह स्पष्ट हो जाता है कि तत्काल समाधान संभव नहीं है, तो कीमतें फिर बढ़ जाती हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार अस्थिरता के बावजूद, भारत अब तक उपभोक्ताओं को वैश्विक ऊर्जा कीमतों के पूरे दुष्प्रभाव से बचाने में सफल रहा है।

उन्होंने कहा, "सरकार ने 76 दिनों तक लोगों को राहत दी, जिसके दौरान कीमतें नहीं बढ़ाई गईं। लेकिन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को प्रतिदिन लगभग 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा था। यह कब तक जारी रखा जा सकता था?"

इससे पहले 23 मई को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में संशोधन किया गया था, जब ओएमसी ने पेट्रोल के दाम 0.87 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल के दाम 0.91 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए थे।

इस बीच, अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए संभावित शांति समझौते की उम्मीदों के बीच वैश्विक तेल कीमतों में पांच प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने तत्काल किसी बड़ी सफलता की संभावना को कमतर बताया है।

इस वृद्धि के बाद दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये (+2.61) प्रति लीटर और डीज़ल 95.20 रुपये (+2.71) मिलेगा। कोलकाता में पैट्रोल के दाम 113.51 रुपये (+2.87) प्रति लीटर तथा डीज़ल के दाम 99.82 रुपये (+2.80) प्रति लीटर हो गए हैं। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपये (+2.72) प्रति लीटर और डीज़ल 97.83 रुपये(+2.81) तथा चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपये (+2.46) प्रति लीटर, डीज़ल 99.55 रुपये (+2.57) प्रति लीटर। वही जयपुर में पेट्रोल 112.44

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- ओएनजीसी की डायरैक्टर सुषमा रावत ने बताया कि जब शांति समझौते की बात होती है, पेट्रोल के दाम गिर जाते हैं, पर, जैसे ही लगता है कि अभी शांति समझौते के आसार नहीं हैं तो दाम फिर बढ़ जाते हैं।
- रावत ने कहा, भारत सरकार ने अभी तक अपने लोगों को तेल के दामों के उतार-चढ़ाव के दुष्प्रभाव से बचाए रखा है, पर आखिर कब तक यह सब कर सकते हैं।

सूरजगढ़ का वीडीओ साढ़े आठ लाख रूपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

जयपुर, 25 मई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए झुंझुनूं जिले की ग्राम पंचायत बेरला पंचायत समिति सूरजगढ़ के ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) राजकुमार को 8 लाख 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी परिवादी के आवासीय भूखंड को व्यवसायिक श्रेणी में परिवर्तित करने और एनओसी जारी करने की एवज में यह रकम मांग रहा था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- परिवादी के आवासीय भूखंड को व्यवसायिक श्रेणी में परिवर्तित करने व एनओसी देने के एवज में पैसे माँग रहा था।

कॉकरोच जनता पार्टी, मीम से हुई शुरुआत डिजीटल युग के राजनैतिक विद्रोह का प्रतीक बनी

राजनैतिक हास्य व्यंग का यह मंच अब व्यवस्था पर युवाओं की नाराज़गी व गुस्सा जताने का जरिया बन गया है

-सुकुमार साह -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 मई। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) इन दिनों सुर्खियों में है। सीजेपी कोई पारंपरिक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि यह व्यंग्य और इंटरनेट से प्रेरित एक विरोध आंदोलन है, जो अचानक युवाओं के गुस्से, व्यवस्था-विरोधी नाराज़गी और डिजिटल युग के राजनीतिक विद्रोह का प्रतीक बन गया है। शुरुआत में जो एक मीम के रूप में शुरू हुई थी, वह तेजी से एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बन गई, क्योंकि यह केवल हास्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि आर्थिक रूप से असुरक्षित और शिक्षित युवाओं की गहरी नाराज़गी को सामने लेकर आई।

इस विवाद की शुरुआत 15 मई 2026 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान की गई कथित टिप्पणियों से हुई। यह सुनवाई वरिष्ठ वकीलों को दिए जाने वाले पदनाम, कथित फर्जी कानून डिग्रियों और कानूनी पेशे के दुरुपयोग से जुड़ी थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने उन लोगों की आलोचना की, जो कथित तौर पर फर्जी और नकली डिग्रियों के जरिए कानून, मीडिया और एक्टिविज़्म जैसे क्षेत्रों में आ रहे हैं और फिर सोशल मीडिया अभियानों, आरटीआई एक्टिविज़्म या सार्वजनिक टिप्पणियों के जरिए सिस्टम पर हमला कर रहे हैं।

यह टिप्पणी तेजी से वायरल हो गई, क्योंकि कई लोगों ने इसे बेरोजगार युवाओं, एक्टिविस्टों और स्वतंत्र मीडिया के खिलाफ एक व्यापक अपमान के रूप में देखा, वो भी ऐसे समय में, जबकि, बेरोजगारी, अधूरी रोजगार व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव पहले से ही राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर विरोध तेजी से बढ़ने लगा।

अगले दिन जस्टिस सूर्यकांत ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया या संदर्भ से बाहर लिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी आलोचना खासतौर पर उन लोगों के खिलाफ थी, जो फर्जी योग्यताओं का इस्तेमाल कर रहे थे, न कि पूरे भारतीय युवा वर्ग के खिलाफ। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मन में भारत के युवाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान है और वे उन्हें विकसित भारत के स्तंभ मानते हैं। लेकिन तब तक यह टिप्पणी अदालत से निकलकर भारत की डिजिटल राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन चुकी थी।

रक्षात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय, जेनरेशन जैन ज़ी के कुछ वर्गों ने इस कथित अपमान को विरोध के प्रतीक में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- 15 मई 2026 को जब भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान बेरोज़गार युवाओं के संबंध में कॉकरोच वाली टिप्पणी की तथा फर्ज़ी डिग्री लेकर एक्टिविस्ट बनने वालों की आलोचना की।
- यह टिप्पणी तेजी से वायरल हुई और लोगों ने इसे बेरोज़गार युवाओं, एक्टिविस्टों व स्वतंत्र मीडिया के अपमान के रूप में देखा।
- उसके विरोध स्वरूप एक हास्य व्यंग्य मीम के रूप में कॉकरोच जनता पार्टी का पोस्ट आया और देखते ही देखते वायरल हो गया। नीट पेपर लीक ने इसे और हवा दी और सोशल मीडिया पर इसके फालोअर्स की संख्या 6 दिन में ही मिलियन्स तक पहुँच गई।
- कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की बढ़ती लोकप्रियता ने राजनैतिक दलों में चिंता पैदा कर दी है। राजनैतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि सीजेपी को मज़ाक समझकर नज़रअदाज़ नहीं करना चाहिए। यह व्यवस्था के प्रति लोगों के गुस्से को दर्शाता है।

असम विधानसभा में यूनिफार्म सिविल कोड विधेयक पेश

गुवाहाटी, 25 मई। असम विधानसभा में सोमवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी), असम 2026 विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य के सभी निवासियों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार तथा लिव-इन संबंधों को लेकर एक समान नागरिक कानूनी ढ ांचा स्थापित करना है। हालांकि, संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

प्रस्तावित विधेयक में धर्म

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- प्रस्तावित विधेयक में सांस्कृतिक विविधता को बनाये रखते हुए पारम्परिक व धार्मिक विवाह पद्धतियों को मान्यता दी गई है।